(b) the details- of those Block Development Headquarters of the above Slates, where telephone facilities could not be made available together with the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNt CATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) The details of the Block Development Headquarters where S.T.D. facilities are available are given in Anncxurc.

(b) the details of the Block Development Headquarters where Telephone facility could not be made available are given in Statement *(see* below)

Priority has been allotted to provision of Telephone facility to District Headquarter, Sub Divisional Head Quarters, Tehsil Head Quarters and Short Distance charging Centre's. All other places having registered demand arc also being covered subject to availability of funds.

Statement

The details of the Block Development Headquarters where S.T.D. facilities are available

State	Block Development Headquarters	
	Total	With STD Facility
Bihar	612	405
Uttar Pradesh	892	435
West Bengal	341	199
Orissa	314	290

The details of the Block Development Headquarters without Telephone facility

State	Block Development Headquarters	
	Total	Without Telephone Facility
Bihar	612	68
Uttar Pradesh	892	64
West Bengal	341	Nil
Orissa	314	Nil

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों द्वारा मुकदमा दायर किया जाना

*179. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या गृह मंत्री 18 दिसम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2687 के लिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच हैं कि वर्ष 1988 में सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने अपने मामलों कें संबंध में दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध मुकदमें दायर किए हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के परिवार की परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए उनको पेंशन अथवा अन्य सुविधाएं देने कें संबंध में विचार करेगी, यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को दिल्ली में दायर किए गए ऐसे अदालती मामलों का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

(ख) इन कार्मिकों को अनुशासनिक आधार पर सेवा से बर्खास्त/सेवामुक्त कर दिया गया था और इन्हें किन्ही पेंशन लाभों की प्राप्ति का अधिकार नहीं हैं । तथाति, अन्य सभी देयताओं का भुगतान कर दिया गया हैं ।

Proposal to Modify/Amend the Article 356 of the Constitution

*180. SHRI P. SOUNDARARAJAN:
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to modifying/amending Article 356 of the Constitution;

(b) if so, whether Government propose to call for an all party meeting before